(2) भैंस का दूध–4 50 रुपए से 5 14 रु० प्रति० कि०ग्रा० (7% वसा तथा 9% ठोस नाट–फैट)

(ग) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

व्यापक फसल बीमा योजना को बढ़ावा दिया जाना

228. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापक फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन में पाई गई कमियों के संदर्भ में ऋण संगठनों, साधारण बीमा निगम तथा "नाबार्ड" की भूमिका की समीक्षा करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) उक्त योजना को बढावा देने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए है, उठाये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) से (ग) सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों और अन्य संबंधित एजेंसियों से जानकारी एकत्र करने तथा सातवीं योजनावधि के दौरान योजना को चलाने में प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर बृहत फ़सल बीमा योजना में कार्यविधि संबंधी परिवर्तन करने की दृष्टि से 23–5–90 को नई दिल्ली में फसल बीमा संबंधी एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई । कार्यशाला द्वारा दिए गए सुझावों में शामिल है --नियमित आधार पर राज्य सरकारों द्वारा अपनी राज्य बीमा निधि को वित्तीय योगदान, ऐसी फ़सलों, जिन्हें विभिन्न ऋण अवधियों की आवश्यकता होती है, को छोडकर बृहत फसल बीमा योजना के अंतर्गत निर्धारित मौसमी विशेषताओं को जारी, रखना ऋण वितरण एजेंसियो द्वारा भारतीय केंद्रीय बीमा निगम को समय पर अपनी घोषणाओं को प्रस्तुत करना, फसल कटाई मशीनरी में सुधार करना, सहकारी ऋण संस्थाओं, वाणिज्यक बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मूल्यांकन यांत्रिकी को सुदृढ करना, ऋण वितरण एजेंसियों द्वारा समय पर सामान्य ऋण सीमा विवरण तैयार करना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतो के अनुसार ही कृषि ऋणों का वितरण, ऋण वितरण एजेंसियों द्वारा समय पर अलग अलग किसानों के दावों की राशि जमा करना, जिला स्तरीय कार्य ढांचा आदि उपलब्ध करा कर बृहत फ़सल बीमा योजना के क्रियान्वयन मे लगी एजेंसियों, के बीच उपयुक्त समन्वय स्थापित करना । इन सुझावों के आधार पर 26–11–90 को सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए । इसको ध्यान में रखते हुए जहा तक बृहत फसल बीमा योजना का संबंध है, सरकार का ऋण संगठनों, साधारण बीमा निगम और नाबार्ड की भूमिका की समीक्षा करने का प्रस्ताव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारंभ करना

229. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश मे चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रायोगिक परियोजनायें प्रारंभ करने के लिए कुछ मंडलों/ब्लाकों का चयन करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हा, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) चावल के उत्पादन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने की संभावना है, और

(घ) इस परियोजना के प्रारंभ होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाए गए "विशेष चावल विकास कार्यक्रम" की पूर्व तैयारी के रूप में